

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1467

जिसका उत्तर मंगलवार 12 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

फेम इंडिया स्कीम

1467. श्रीमती अंजू बाला:

श्री एल.आर. शिवराम गौड़ा:

श्री तेज प्रताप सिंह यादव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को शीघ्र अपनाने और विनिर्माण के कार्यान्वयन स्कीम की वर्तमान स्थिति और कार्यान्वयन की प्रगति क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत कितना आबंटन किया गया है;
- (ग) फेम-II इंडिया स्कीम के कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा क्या है; और
- (घ) देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के संवहनीय विकास हेतु स्थिर नीतिगत ढांचा और खाका सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ₹795 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से फेम-इंडिया योजना (चरण-I) अधिसूचित की। योजना के चरण-I को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बढ़ोतरी ₹895 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ दिनांक 31 मार्च, 2019 तक अनुमत की गई है।

योजना के चरण-I को चार फोकस क्षेत्रों नामतः मांग सृजन, प्रौद्योगिकी मंच, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

योजना के मांग सृजन फोकस क्षेत्र के तहत इस स्कीम के माध्यम से लगभग 2,65,335 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों की सहायता की गई है। उपर्युक्त के अलावा, योजना के प्रौद्योगिकी मंच, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना फोकस क्षेत्रों के तहत अनेक परियोजनाएं अनुमोदित/मंजूर की गई हैं।

आज की तारीख तक फेम इंडिया योजना को कार्यान्वित करने हेतु बजटीय आबंटन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बजटीय आबंटन
1.	2015-16	₹ 75 करोड़
2.	2016-17	₹ 144 करोड़
3.	2017-18	₹ 165 करोड़
4.	2018-19	₹ 145 करोड़ (संशोधित)

फेम इंडिया योजना का चरण-I अब तक सफल रहा है और योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रस्तावित योजना का दूसरा चरण तैयार किया गया है। (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना (फेम इंडिया) के चरण-II में बाजार सृजन और मांग संग्रह के द्वारा ईवी के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने तथा सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। मसौदा योजना में चार्जिंग अवसंरचना, ईवी प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान एवं विकास और अधिक स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के प्रावधान सहित ईवी उद्योग के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना है। (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना (फेम इंडिया) के चरण-II को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।